



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1864)

Name of Candidate	RAVI		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	168117
Center	Delhi	Date	25/12/21

INDEX TABLE		
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	
Total Marks Obtained:		
Remarks:		

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI** इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

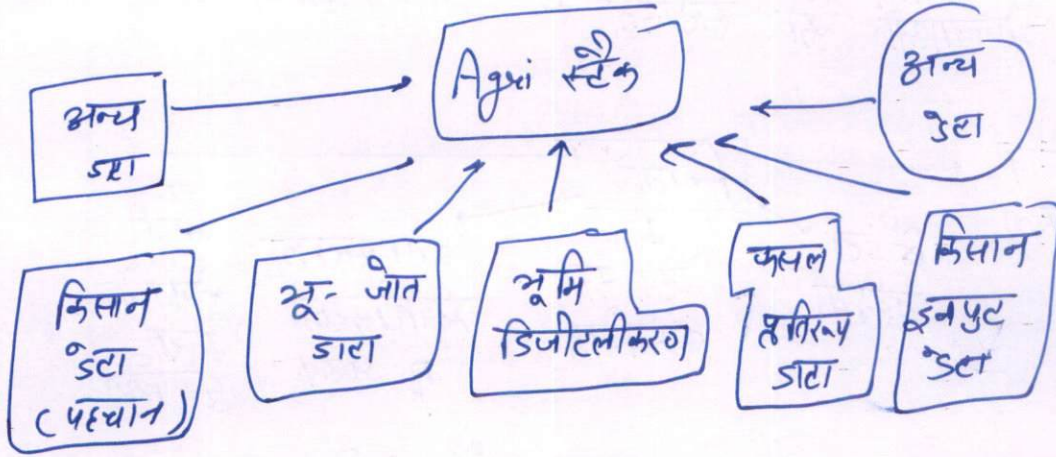
All the Best

1. Agristack can serve as a foundation to build innovative agri-focused solutions, thus enabling creation of a better ecosystem for agriculture in India. Comment. Also, discuss the concerns associated with it.

(150 words) 10

एग्रिस्टैक अभिनव कृषि-केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य कर सकता है, इस प्रकार यह भारत में कृषि के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को सक्षम बनाता है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए।

हाल ही में नीति आयोग द्वारा हबि से संबंधित संग्रह डेटा संरचना को संग्रहित कर एक व्यापक डेटा डैशबोर्ड लगीस्टैक बनाने का सुझाव दिया है।



महत्व व समाधान पक्ष

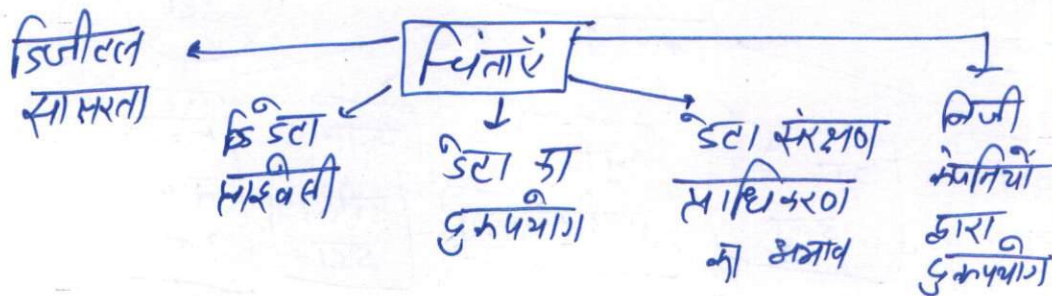
(i) किसानों पर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में।

↳ उदा. :- पूर्वोक्त में चावल, गेहूँ आदि कसलों पर नीति।

↳ द्वितीय हरित क्रांति को सफल बनाना।

(ii) नीति क्रियान्वयन :- संस्थानत्री कसल बीमा योजना जैसी नीति योजनाओं का उचित सूचकांकन।

- (iii) विखंडित यू-डेटा, यू-जोनों का डिजिटलीकरण व समन्वय करने में :- डेटा डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम।
- (iv) मांग आधारित दृष्टिकोण :- जल, बीज, खस आदि इनपुट समाधान।
- (v) सहस्रि व सेवाधन सुनिश्चन
- (vi) निजी कंपनियों व क्षेत्र को लाभ :-
- (vii) प्रोत्साहनों को सरलता से लागू करना।



आंग की राह :- सहमति आधारित दृष्टिकोण है।

- ↳ डेटा का उचित वर्गीकरण है।
- ↳ समाजी डेटा संग्रहण स्थापना।
- ↳ निजी कंपनियों की जवाबदेहिता व परदर्शिता।

B. J. श्रीरुवा समिति की सिफारिशों पर बना डेटा संग्रहण विधायक को पारित कर समाजी क्रियान्वयन समय की मांग है।

2. Despite the advantages of geothermal energy, it has not been adopted on a wide scale in India. Discuss. (150 words) 10

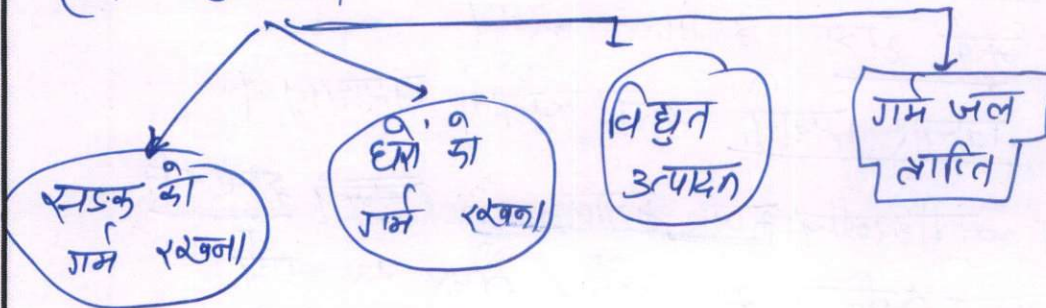
भूतापीय ऊर्जा के लाभों के बावजूद, इसे भारत में व्यापक पैमाने पर नहीं अपनाया गया है। चर्चा कीजिए।

भू-तापीय ऊर्जा से तात्पर्य पृथ्वी के अंदर आंतरिक सक्रियता व भौमा से उत्पन्न अवशिष्ट ऊर्जा के प्रभावी मानवीय प्रयोग से है।



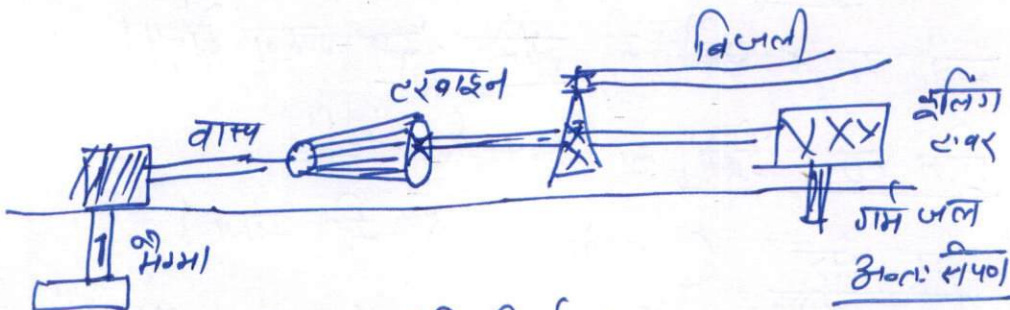
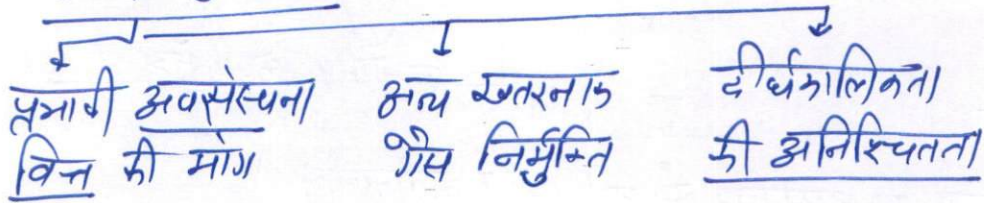
लाभ

- (i) ऊर्जा का असीमित स्रोत। (नवीकरणीय)
- (ii) ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कम गहन है।
- (iii) ग्रीन हाउस जैसे का उत्सर्जन नहीं।
- (iv) 'कम क्षेत्र' (प्लॉट हेतु) की मांग।
- (v) भारत में वृहत उपलब्धता (10,000 MW)।
- (vi) बहुआयामी प्रयोग



भारत में प्रयोग चुनौतियाँ

- (i) व्यापक अन्वेषण नहीं :- भू-सर्वे विभाग के पास तकनीक, वित्त व मानव संसाधन कमी।
- (ii) ड्रिलिंग हेतु तकनीक का अभाव।
↳ आयात आकर्षक।
- (iii) कठोर व दुर्गम भू-भाग :- लकड़ाख आदि क्षेत्र।
- (iv) अन्य चुनौतियाँ



भूगर्भ की राह :- व्यापक नीति निर्माण।

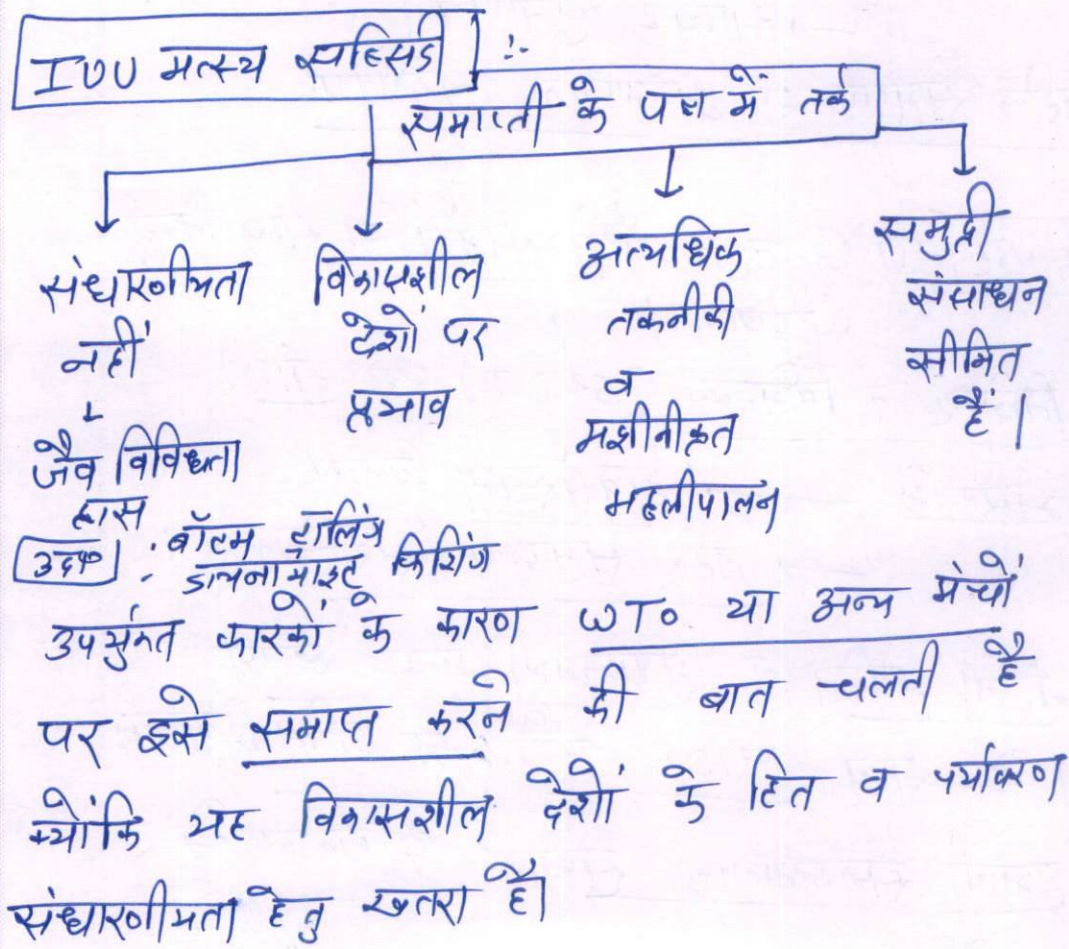
- (i) 'मैक इन इंडिया' द्वारा तकनीक निर्माण।
- (ii) निजी क्षेत्र आमंत्रित करना।
- (iii) नवाचार मिशनों द्वारा चुनौती समाधान।
- हालिया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसंधान नीति के अनुसंधान अविश्व का राष्ट्रीय नवाचार पर ध्यान देना चाहिए।

3. While the WTO seeks elimination of subsidies that contribute to IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, there are multiple concerns around it. Discuss while highlighting India's stand on the issue.

(150 words) 10

जहाँ IUU (अवैध, अनरिपोर्टेड या असूचित और अनियमित) मत्स्यन सब्सिडी को समाप्त करना संधारणीय मत्स्यन को सुनिश्चित करने हेतु परिकल्पित है, वहीं इसके इर्द-गिर्द अनेक चिंताएं विद्यमान हैं। इस मुद्दे पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुए इसकी विवेचना कीजिए।

भारत मछलीपालन का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है व विश्व के कुल मत्स्यपालन में 7.7% हिस्सेदारी रखता है।



भारत की चिंताएं

→ ① तरीय समुदाय पर सभाव :- 2 करोड़

लोगों की आजीविका मित्र (5 करोड़ अल्पमज)।

- ② GDP में योगदान - कुल GDP में 1.5% योगदान।
- ③ पोषण सुरक्षा - Hidden hunger व 'ग्रीन फूड ओदोलन' के अनुरण।
- ④ भारत की सीमित समता
 - ↳ सबिली प्रदान करने की।
 - ↳ आर्थिक चुनौतियाँ।
- ⑤ तरील समुदाय की आजीविका चुनौतियाँ

भारत की राह (i) G-77 जैसे समूहों के साथ लेबर सौदषाज।

(ii) विशिए व विमैरक (S&DT) पर भांग।

(iii) भारत में — अवसंरचना विकास
↳ तरील समुदाय सशक्तिकरण।

नीली क्रान्ति व प्रधानमंत्री मत्स्य सेपद
योजना के साथ FIDF फंडों का उचित क्रियान्वयन
कर पुत्रावी संरचनात्मक सुधार दीर्घकाल में
आवश्यक हैं।

4. There is a view that the current agricultural policies in India are biased against rainfed agriculture. Comment. Also, identify government initiatives in this regard. (150 words) 10

यह विचार दिया जाता है कि भारत में वर्तमान कृषि नीतियां सिंचित कृषि के पक्ष में हैं। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकारी पहलों की पहचान कीजिए।

भारत में संवर्ण कृषि क्षेत्र का 48-1% भाग सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। बाकी सभी हिस्सा वर्षा सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत है।

कृषि नीतियाँ व सिंचित क्षेत्र

- ① नीति-निर्माण :- हरित क्रान्ति का लाभ पेजस, हरियाणा जैसे राज्यों को हुआ है।
- ② सिंचित :- इनपुट सिंचित - खाद, खरिया का प्रयोग सिंचित भूमि में ही अधिक।
- ③ विपणन समर्थन :- कुल MSP सरकारी खरीद में-
 - ↳ सिंचित फसलें - गेहूँ, धान = 90% हिस्सा।
 - ↳ सिंचित राज्यों से अधिकतर खरीद।
 - ↳ तिलहन, दलहन जैसे सूखा प्रभावी फसलें (तिलहन की सरकारी खरीद = 0.9%
दलहन की खरीद = अधिकतर उत्पादन का 10%)
- ④ योजनाएँ :- प्रधानमंत्री कृषि सिंचित योजना का प्रभाव सिंचित क्षेत्रों पर अधिक।
- ⑤ अनुसंधान व्यय :- अधिकतर व्यय सिंचित

कसलों पर
इस प्रकार इस संबंध में कहा जा सकता
है कि उपरोक्त नीतियाँ न योजनाएँ सिंचित क्षेत्रों
के पक्ष में हैं।

सरकारी पहल

असिंचित क्षेत्र लक्ष्य

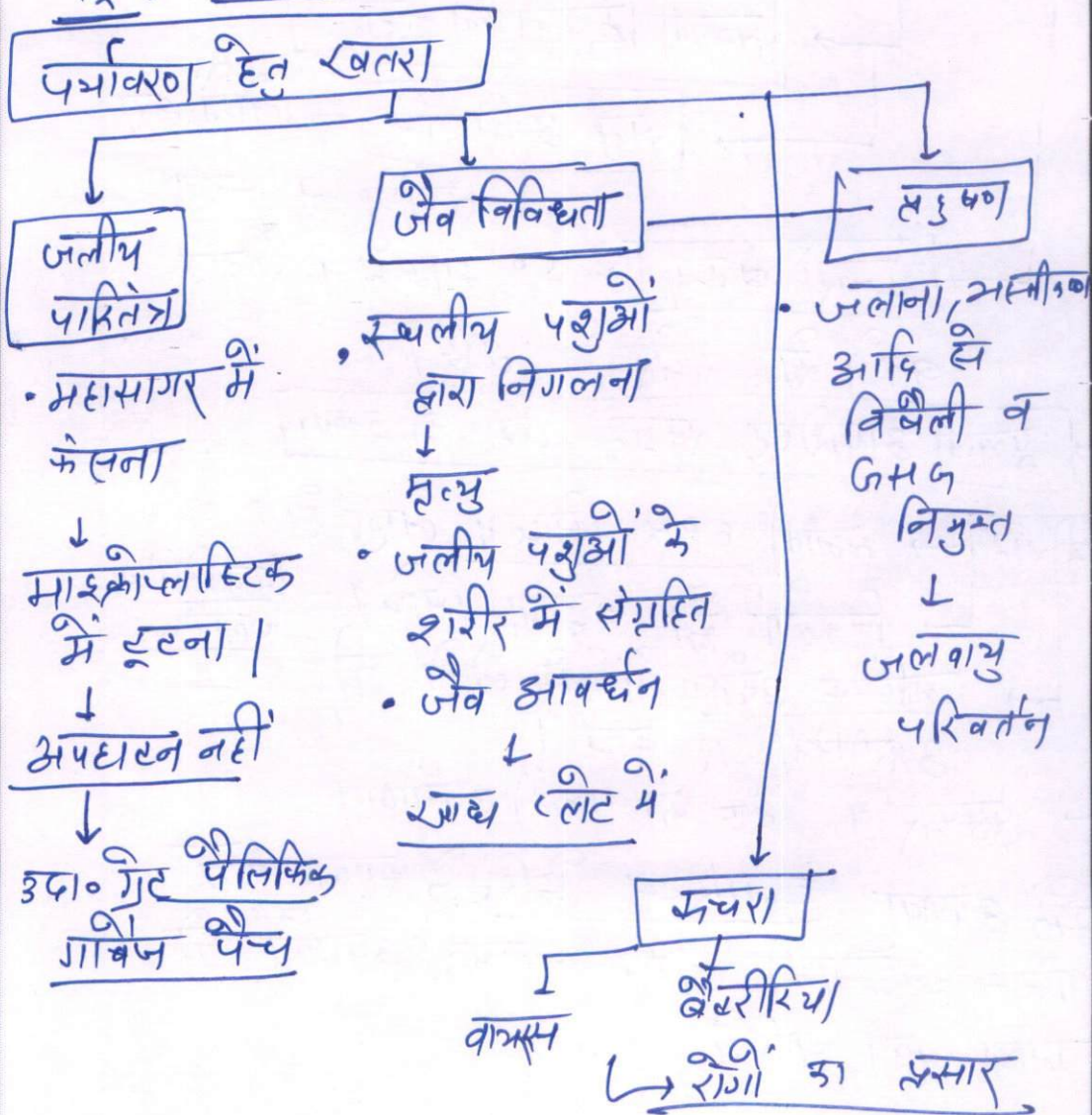
- ① सूखा क्षेत्र विकास योजना:-
- ② PMKSY :- 'पर ड्रॉप मॉर ड्रॉप'
- ③ दलहन-तिलहन खरीद तहफे
↳ PM आशा योजना।
- ④ पूर्वी राज्य व पूर्वोत्तर
↳ द्वितीय हरित क्रांति।
↳ कोस मिशन।
- ⑤ जैविक खेती प्रोत्साहन
↳ जीरा वजत नेचुरल फार्मिंग
↳ राष्ट्रीय स्वतंत्र कृषि मिशन।

इस प्रकार उपरोक्त असिंचित क्षेत्रों के लिये
एक व्यापक, समर्पित लक्षित नीति निर्माण के
साथ क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों की जरूरत है।
असिंचित क्षेत्रों के अनुसंधान असिंचित
क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है।

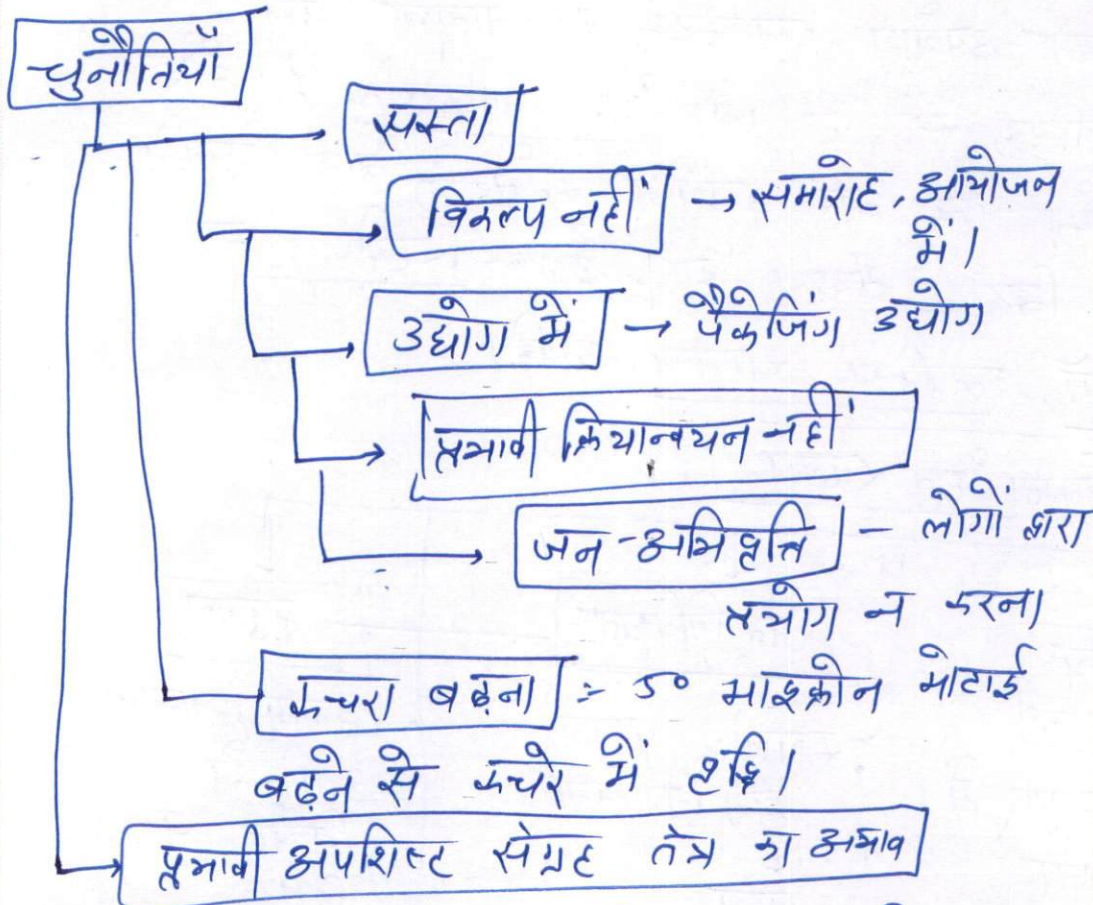
5. Enumerate the major causes behind marine heatwaves. Also, discuss their impact on the ocean ecosystem. (150 words) 10

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक क्या हैं और ये पर्यावरण के लिए खतरा क्यों हैं? भारत में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

एकल-उपयोग प्लास्टिक से तात्पर्य वे प्लास्टिक हैं जो गैर-नवीकरणीय हैं और जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फेंकने का विकल्प बचता है। उदा०- डिस्पोजल कप, स्ट्रॉ, प्लास्टिक चम्मच आदि।



भारत में हालिया प्लास्टिक अपशिष्ट नियम में मोटाई बढ़ाने (120 माइक्रोन) जैसे पर्यावरण कार्यक्रम पलायन है -



आगे की राह

- समावी EPR सिस्टम लागू हो।
- विकल्पों को बढ़ावा जाये। - जैसे निम्नीकरण प्लास्टिक
- प्लास्टिक उद्योग में लैग लोगों की आजीविका पर कार्य।
- पुस्तकार व दंड का सख्ती उपयोग।
- अपना अलावा 'प्लास्टिक क्रेडिट' के साथ नए प्लास्टिक इकाई-नोमी जैसे नवाचारी उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

6. Aseismic structures are touted as a viable solution to combat earthquake destruction. In this context, highlight the need of a National Program on Seismic Retrofitting of Buildings and Structures in India. (150 words) 10

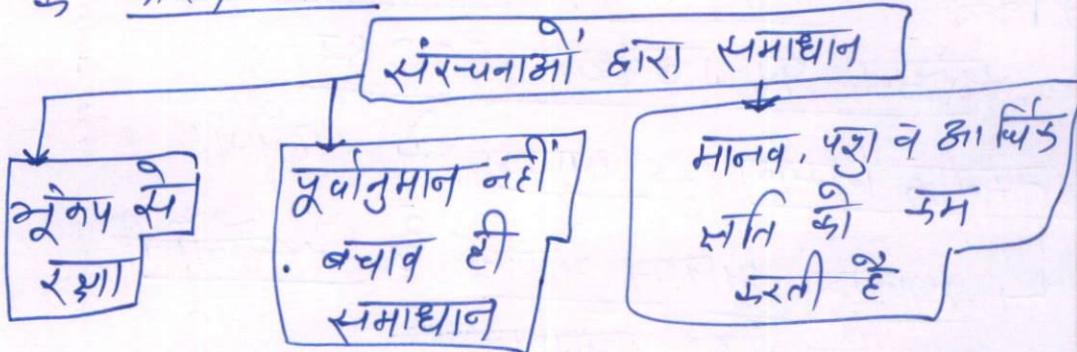
भूकंप के विनाश से निपटने के लिए भूकंपीय संरचनाओं को एक व्यवहार्य समाधान के रूप में माना जाता है। इस संदर्भ में, भारत में भवनों और संरचनाओं के भूकंपीय पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए।

NDMA के अनुसार भारत का 57. भाग भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।

भूकंपीय संरचनाओं का खभाव



• कहा जाता है कि भूकंप द्वारा नहीं बल्कि इमारतों के कारण मानवों की जान जाती है।



कार्यक्रम की आवश्यकता

(i) 'सिडर फ्रेमवर्क लक्ष्य' के अनुरूप

- ↳ GDP प्रति उम्र करने हेतु।
- ↳ मानव हानि में कमी
- ↳ प्रभावित लोगों की संख्या में कमी।

(ii) भारत की सुवेद्यता

- अत्यधिक जनसंख्या
- जनसंख्या घनत्व अधिक
- टेक्नॉलॉजिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में
अवस्थित।

→ हिमालय ग्रैनिथर्ड - भारतीय प्लैट
→ भूशों की उपस्थिति।

(iii) विनाशशील देश :- आपदा हानि अधिक
↳ क्याव ही उपचार।

आगे की राह (i) केन्द्र में प्रभावी कार्यक्रम अपनाना।

(ii) वित्त - आपदा बीमा, PPP, आपदा रोधी
संरचना पर गठबंधन (CDRI)

(iii) तकनीक निर्माण -> जापान से सहयोग।

↳ प्रधानमंत्री आवास योजना के 'टेक्नोलॉजी
स्व मिरान' का उपयोग।

इस प्रकार G-7 के बिल बैंक वर्ल्ड
कार्यक्रम से सहयोग के साथ प्रभावी, लचीली
संरचना का निर्माण भारत की सुवैधता को
कम कर सकता है।

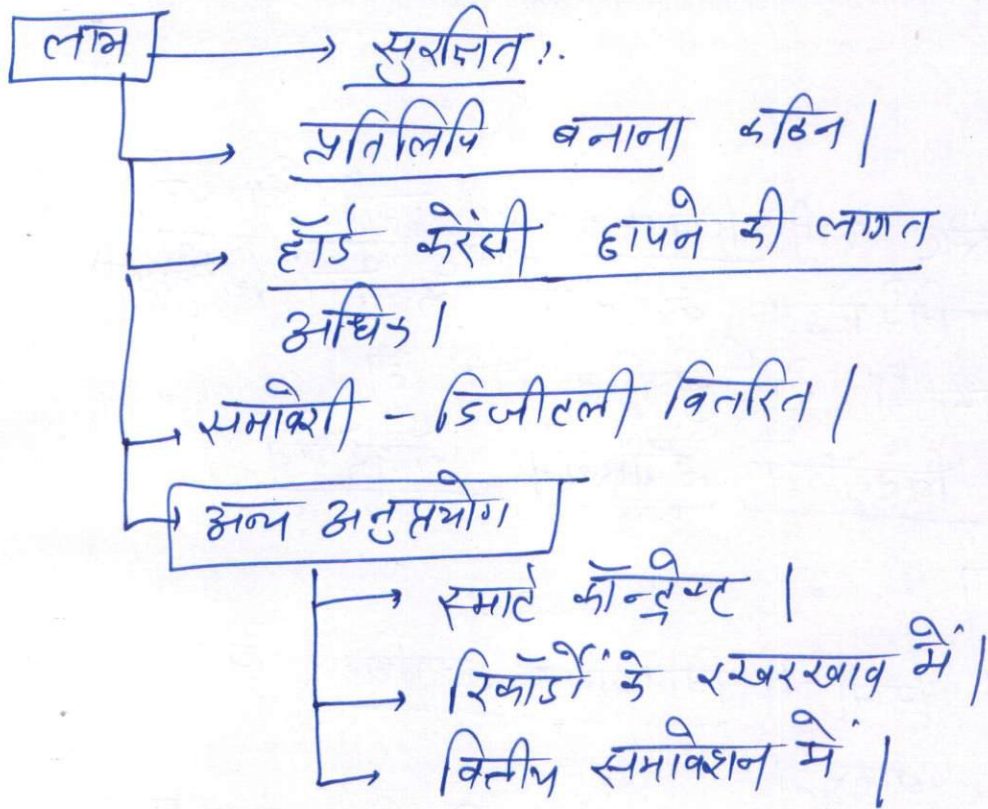
7. Despite the risks associated with cryptoassets, their underlying advantages should not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

क्रिप्टो-एसेट्स से जुड़े जोखिमों के बावजूद, उनके अंतर्निहित लाभों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। चर्चा कीजिए।

क्रिप्टो एसेट्स ऐसी परिसंपत्तियाँ या सुवस्तुओं को कहते हैं जो विनिश्चित बही-खाते के साथ, क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीकों से सुवर्णित होती हैं।
उदा०- बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकोइन ।

जोखिम

- (i) किसी भी विनियामक क्षेत्राधिकार से बाहर ।
- (ii) स्पैरियुलेशन के द्वारा निश्चित सुवस्तु पर प्रभाव ।
- (iii) निश्चित अव्यवस्था के समानान्तर व्यवस्था सृजन ।
- (iv) कोई उत्पादक कार्य नहीं।
- (v) अपरिवर्तनीय व Irreversible
↳ गलत लेन-देन में संशोधन नहीं।
- (vi) तकनीकी मुद्दे
↳ जलवायु परिवर्तन → अधिक ऊर्जा गहन प्रक्रिया।
↳ डेटा स्टोरेज का मुद्दा ।



आगे की राह

- (i) सरकारी विनियमन सृजन
- (ii) सुभाष चन्द्र गर्ग समिति
 - ↳ सरकारी मुद्रा (डिजीटल) जारी की जाए।
- (iii) अर्बेच लेन-देन पर प्रतिबंध लगाना।

अंतः - चीनी की डिजीटल मुद्रा की भाँति
RBI को भी सचोग कर लाभ-देहन करना
चाहिये।

8. Virtual Reality and Augmented Reality (VR and AR) have massive innovation potential across a wide range of industries and research fields in India. Discuss. (150 words) 10

हालांकि, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में हमारे कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की अपार क्षमताएं हैं, लेकिन भारत में इसके विकास के समक्ष अनेक बाधाएं विद्यमान हैं। चर्चा कीजिए।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य जीव विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें जीवित जीवों का प्रयोग कर कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है और, इनका प्रयोग मानव कल्याण में किया जाता है। उदा० GM फसलें।

मुद्दा समाधान

समाधान

(i) अल्प उत्पादकता :- उत्पादक फसल विकास

(ii) कीट व रोगों की समस्या :- बी.टी. बैंगन

(iii) कृषि फसलों में पोषक तत्व समस्या :- गोल्डन राईस (विटामिन - A)

(iv) जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :- सूखा प्रतिरोधी फसल निर्माण
- हालिया गोंडू की Rht - 1 प किस्म।

(v) कम आजीविका व आय :- उच्च उत्पादन से अधिक आय।

(vi) जल की कमी :- प्रतिरोधी किस्म निर्माण

भारत में वाद्याएँ

- (i) कृषि R&D में कम व्यय :- कृषि GDP का केवल 1%।
- (ii) मानव संसाधन की कमी :-
- (iii) जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा पर अधिक फोकस।
- (iv) कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण नहीं :-
 ↳ कृषि कॉलेजों में - पुराना पाठ्यक्रम।
 ↳ आधुनिक लैब नहीं।
 ↳ कित्त की कमी।
 ↳ छात्रों में अनुसंधान अक्षिति
- (v) मुख्य फोकस चावल, गेहूँ जैसी फिम्सों पर

आगे की बात → (i) शिक्षा व अनुसंधान :- कृषि विश्व-विद्यालय प्रोत्साहन।

- (ii) प्रधानमंत्री रिसर्च फंड के अन्तर्गत लाना।
- (iii) नवाचार कल्चर का विकास।
- (iv) स्टार्टअप प्रोत्साहन।
- (v) कृषि स्नातकों के अनुसंधान प्रोत्साहन।

अन्ततः 'बायो कार्म मिशन' की भाँति
'बायो कृषि मिशन' की संकल्पना के प्रोत्साहन
दिया जाना चाहिए।

9. Discuss the role and functions of Narcotics Control Bureau (NCB) and examine whether the NDPS Act, 1985 needs to be remodelled.

(150 words) 10

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए तथा परीक्षण कीजिए कि क्या NDPS अधिनियम, 1985 को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना NDPS
अधिनियम के सभावी स्थितीकरण के साथ-साथ
मादक द्रव्यों के उत्पादन, वितरण, उपयोग,
व्यापार पर नियंत्रण स्थापना के लिए गृह मंत्रालय
के अन्तर्गत की गई थी। (गृह मंत्रालय)

भूमिका व कार्य

- (i) मादक द्रव्यों पर सभावी नियंत्रण।
- (ii) अफीम आदि के सीमित उत्पादन का विनियमन।
- (iii) उत्पादन पट्टे देना व सभावी निगरानी।
- (iv) अवैध व्यापार की आसूचना जैसी के
रूप में काम करना।
- (v) दवाओं के उपयोग, व्यापार (अवैध),
स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगाना।

NDPS अधिनियम 1985 :- मादक द्रव्यों के
विनियमन व नियंत्रण की सार्वनी वन्परिखा
व संयुक्त राष्ट्र के अग्रिसम्प्रीं का

पालन करने हेतु स्थापना |

भूमिगत व कार्य

- ① विनियमन व फ्रेमवर्क पर कार्य।
- ② मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध।
- ③ मांग व आपूर्ति संबंधन पर बल

नवीनीकरण प्रस्ताव

- ① भारत की बढ़ती सुमैद्यता - गोल्डन ट्रायंगल व क्रिसैट के पारगमन मार्ग पर।
- ② नदी पर रोक के

साथ सभावी नशा-मुक्ति कार्यक्रमों में भूमिका नहीं।

- ③ मादक पदार्थों का बढ़ता सेक्टर :- NIMS की ड्रग उपयोग रिपोर्ट - 8.5 करोड़ भारतीय सेक्टर

- ④ बढ़ता तकनीकी प्रयोग।

उपभुक्त कारकों के अलावा में अधिनियम में कई प्रावधानों के साथ सभावी तकनीकी रोकथाम, आधुनिक समय के अनुरूप तकनीकी प्रावधान व नशा-मुक्ति मौखिक सहायता व पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रावधान बनाये जायें चाहिए।

10. Recent events have raised concerns around the issue of surveillance in India. Do you think surveillance is a necessary evil to tackle crime and terror? Discuss the various arguments on the issue. (150 words) 10

हाल की घटनाओं ने भारत में निगरानी के मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्या आपको लगता है कि अपराध और आतंक से निपटने के लिए निगरानी एक आवश्यक बुराई है? इस मुद्दे पर विभिन्न तर्कों की विवेचना कीजिए।

निगरानी से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन की गतिविधियों पर नज़र व सत्तावी अवलोकन रखने से है। भारत में टेलीग्राफ अधिनियम व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सरकार द्वारा इसे संपादित किया जाता है।

आवश्यकता

- ① आंतरिक सुरक्षा के:
 - बढ़ते खतरों।
 - लॉव कुल्फ आर्टक।
- ② अपराध रोकथाम हेतु:-
 - साबर अपराध।
 - इंटरनेट हेतु स्पीच।
- ③ राज्य विरोधी गतिविधियों पर निवारक उपाय:-
 - आतंकी योजना बनाना।
 - हालिया दिल्ली में आतंकी परकटने का मामला।

युक्तियाँ

- ① निजता का हनन:-
 - पुरटास्वामी वाद के निर्णय का पालन नहीं।
- ② प्रेस की स्वतंत्रता का सत्तावी
- ③ सत्तावी विनियामक प्राधिकरण का अभाव।
- ④ कार्यकारी द्वारा विधि की सन्धक प्रक्रिया का पालन न किया जाना।

- ④ नवीन तकनीकी खतरों :-
• अनाम हमले

हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा संपर्कों में निगरानी आवश्यक बुराई है जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी सीमित किया है।

भाग 51 14E (i) के एस. पुल्टा स्वामी वाद के अनुसृत्य मानुपातिकता सिद्धान्त पालना।

(ii) डेटा संरक्षण विधेयक पारित करना।

(iii) सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना।

(iv) न्यायपालिका की सत्ता को मजबूत करना।

(v) व्यक्तिगत डिजिटल जागरूकता सृजन करना।

इस प्रकार 'ऑरवेलियन स्टेट' या 'निगरानी राज्य' बनने से व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार व राष्ट्रीय सुरक्षा में उचित संतुलन बनाना आवश्यक है।

11. The decision to grow a particular crop by a farmer is affected by various factors other than the yield of a crop. Discuss this statement and assess the need for bringing a change in the cropping pattern in India.

(250 words) 15

एक किसान द्वारा किसी विशेष फसल को उगाने का निर्णय उक्त फसल की उपज के अतिरिक्त विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा भारत में फसल पद्धति (क्रॉपिंग पैटर्न) में परिवर्तन लाने की आवश्यकता का आकलन कीजिए।

किसी भी फसल को उगाने के लिये अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं -

(i) उपज का होना

(ii) इनपुट उपलब्धता

जैसे पंजाब, हरियाणा में - जोंडू व चावल की उपज - उर्वरक, बीज व मीम-जल के साथ सिंचाई उपलब्धता पर निर्भर है।

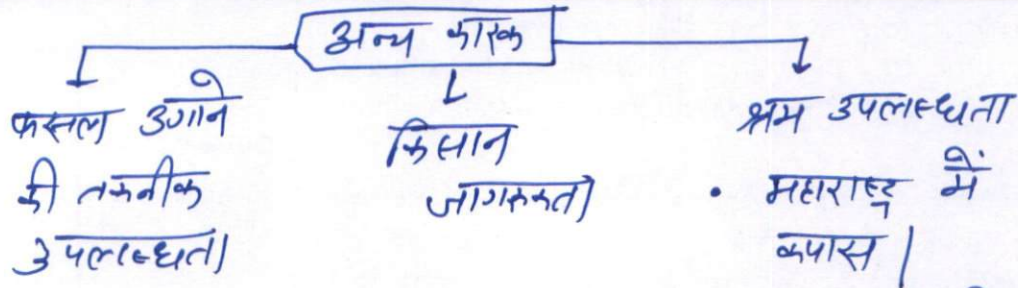
(iii) जलवायु :- कश्मीर में केसर की हथि।
• राजस्थान में बाजरा की हथि।

(iv) सरकारी नीति - MSP आदि

- हरित क्रांति में जोंडू व चावल का परिचय
भारत में सीमित होना

(v) उच्चावच :- चावल की खेती का पूर्वोत्तर
कालों पर।

(vi) बाजार समर्थन :- अनेक उत्पादक फसलों जैसे
दलहन, मूँट अनाजों न न उगाया जाना।



इस प्रकार केवल उपज ही फसल उगाते के निर्णय में एकमात्र कारक नहीं है।

भारत में फसल पैटर्न में परिवर्तन की ज़रूरत

① विषय फसल परिवर्तन

- ↳ पंजाब, हरियाणा जैसे कम जल उपलब्ध राज्यों में धान की कृषि :-
 - ↳ जल-सूदा लक्ष्य।
 - ↳ उर्वरक उपयोग।

② फसल विविधीकरण का अभाव

- ↳ धान व गेहूँ केन्द्रित।

③ जलवायु अनुकूल कृषि नहीं

- ↳ उत्तरी राजस्थान में धान उगाना।

④ किसान डिस्ट्रेस - महाराष्ट्र के निर्धन आदि में अकरी फसल उगाना।

⑤ पोषण सुरक्षा - गेहूँ अनाज, दाल का उत्पादन बढ़ाना।

⑥ उपभोक्ताओं की मूल्य सुरक्षा

↳ जल, सखी उत्पादन बढ़ाना।

⑦ सरकारी, स्टिस्टि बिल की तर्कसंगत बनाने हेतु।

⑧ क्षेत्रीय असमानता को उचित करना :-

आगे की राह → (i) प्लानमेट स्मार्ट रूबि प्रोत्साहन।

(ii) एग्री-प्लानमेटिक प्लानिंग।

(iii) MSP व स्टिस्टि युक्तिकरण

↳ DBT Based स्टिस्टि

↳ दाल, तिलहन, मूँटे अनाज शामिल।

(iv) प्रौद्योगिकी विकास

↳ कंस, प्लोरीकल्चर प्रोत्साहन।

(v) इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रोत्साहन।

इस प्रकार नई क्षेत्र आधारित नीतियाँ

के साथ, तकनीक-विकास व किसान जागरूकता

के साथ वांछित परिवर्तन किया जाना चाहिए।

12. Identifying the importance of livestock in the Indian agricultural economy, enumerate the steps taken by the government in this regard. Also, discuss the potential impact of climate change on the livestock sector.

(250 words) 15

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व को चिन्हित करते हुए, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, पशुधन क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

भारत की कुल GDP में पशुधन का 34% योगदान है व सबसे अधिक पशु भी भारत में पाये जाते हैं।

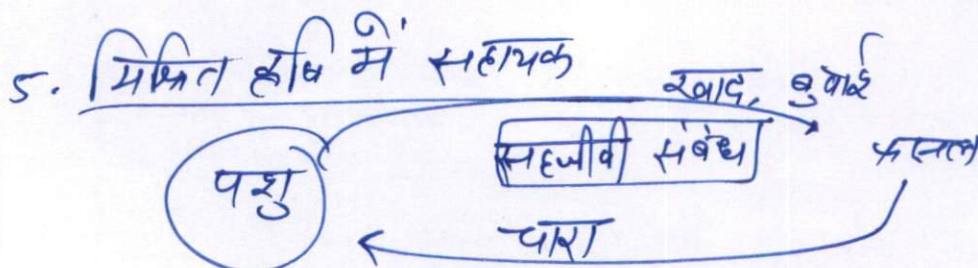
महत्व

1. आय सुरक्षा :- लघु व सीमांत किसान की आय में 16% योगदान।
2. आर्थिक हद :- पिछले 5 वर्ष में 8.15% से CAGR।
3. पोषण सुरक्षा :- विश्व में भारत का दूध उत्पादन में छठम स्थान।

4. आय जोखिम (आपदा में)

सूखा - फसल खराब
पशु - 'अकाल रिजर्व'

Bank
on
hooves



6. अचल संपत्ति के रूप में क्लियर के पास

7. हाई प्रोड्यूसिंग बकरी-गैड :- पोषक दूध, दस चारा
↳ गरीब की जाय।

भारत सरकार के कदम

विकासोन्मुख

1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
2. नेशनल प्रोग्राम ऑन
बोवराइन ब्रीडिंग व
डायरी इम्प्रूवमेंट
3. राष्ट्रीय गोकुल
मिशन
4. पशुधन मंत्रालय :-

स्वास्थ्य

- पशु स्वास्थ्य व रोग निगरानी
कार्यक्रम
- एकीकृत कृषि मजुर्दान
कार्यक्रम
- FMD व इन्फ्लुएन्जा
निंत्रण कार्यक्रम
- ई - पशुधन संजीवनी
- गोकुल स्वास्थ्य पत्र

वित्त व

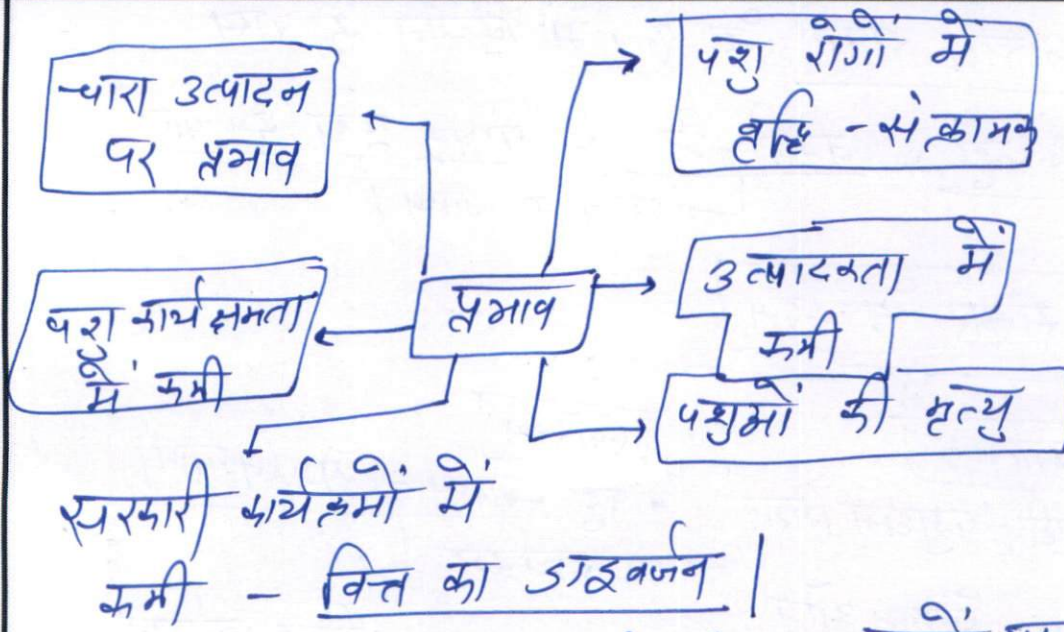
अवसंस्थान

• पशुपालन अवसंरचना विकास
फंड (AMDF)
: डायरी अवसंरचना विकास फंड

• पशुधन क्रेडिट कार्ड

• पशु स्वास्थ्य सूचना पोर्टल (INAPM)

जलवायु परिवर्तन की संभावित प्रभाव



इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का पशुओं पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- (i) अनुसूचन उपाय : उन्नत नस्ल अनुसंधान
↳ जैव टेम्नालोजी प्रयोग।
- (ii) पशु-कार्मों की स्थापना
↳ अनुसूचित ताप व आर्द्रता।
↳ उन्नत चारा व पोषक तत्व

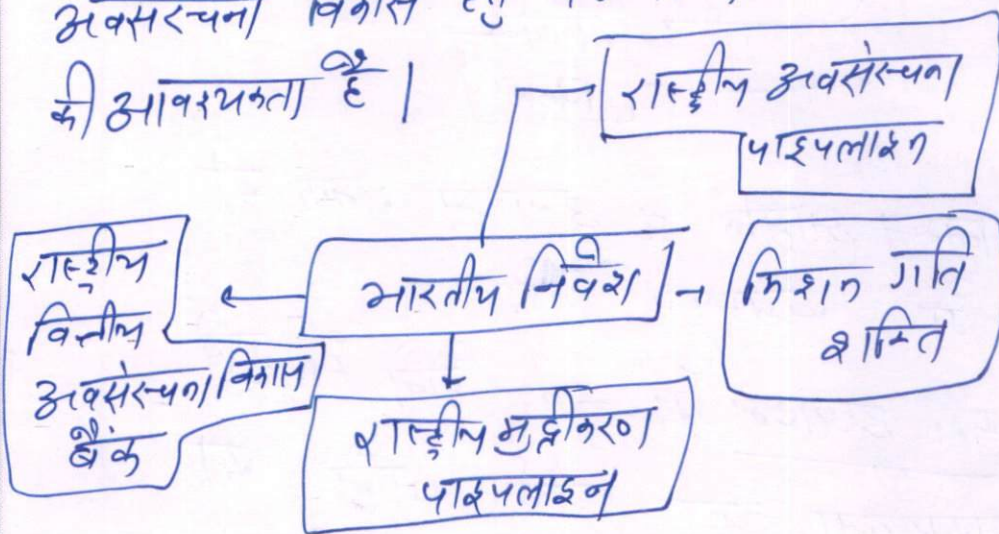
इसके अलावा 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' में जलवायु परिवर्तन घटक का समावेश करना भी आवश्यक है।

13. It has been argued by some economists that supply creates its own demand. In this context, discuss the merits and demerits of reliance on investment in infrastructure to boost the Indian economy.

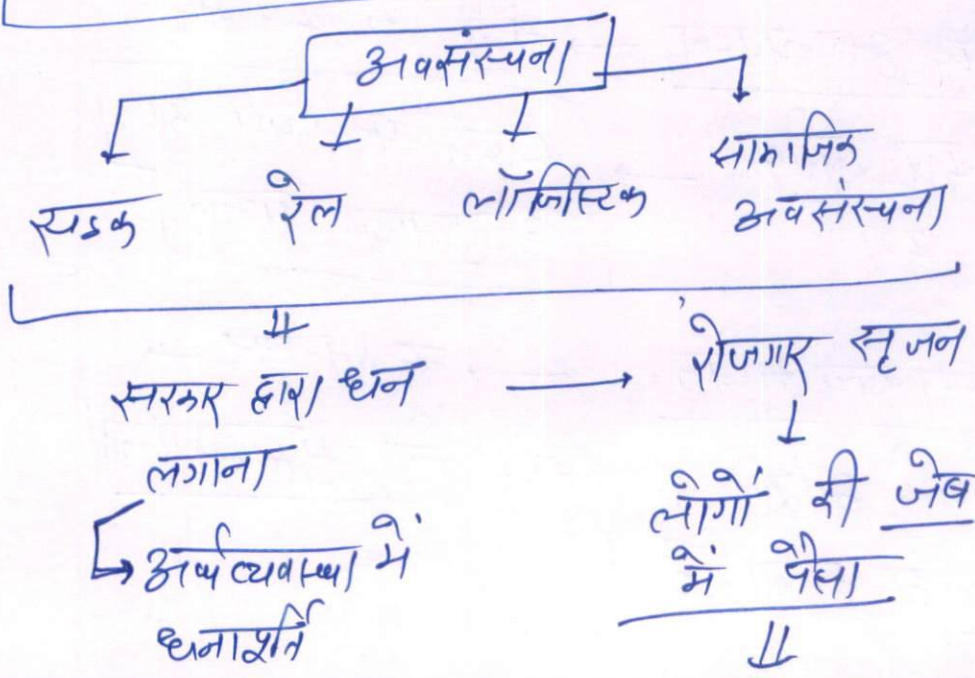
(250 words) 15

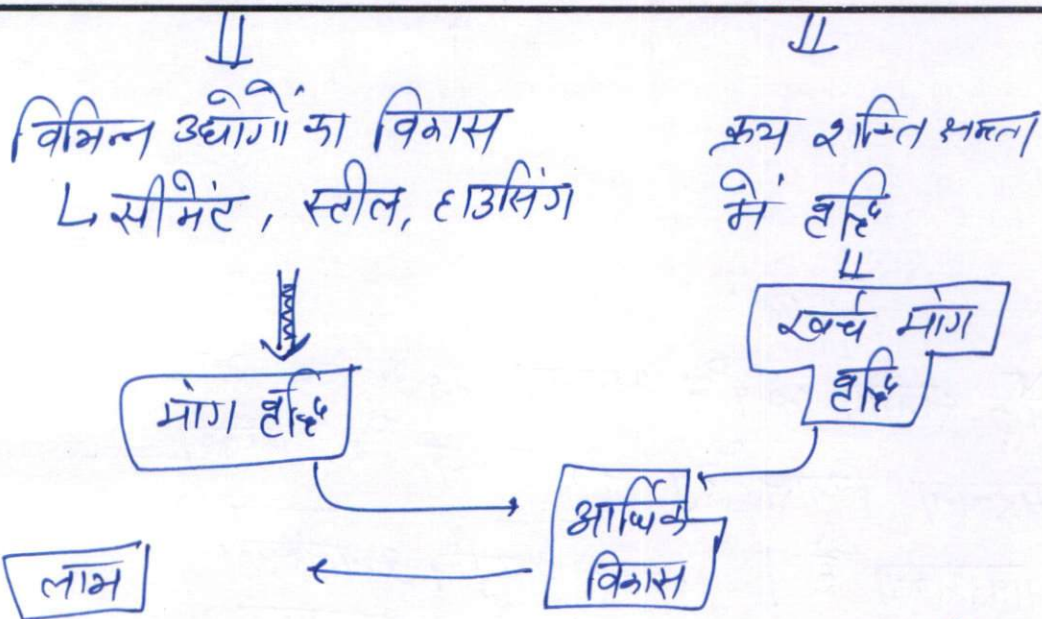
कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आपूर्ति अपनी मांग को स्वयं सृजित करती है। इस संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश पर निर्भरता के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए।

आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार 2030 तक भारत की अवसंरचना विकास हेतु 4.5 Tr \$ के निवेश की आवश्यकता है।



अवसंरचना निवेश व मांग सृजन पर





दोष :- निम्न आपूर्ति व उत्पादन क्षमता की स्थिति में समस्याएँ जैसे -

(i) कृषि उत्पादन में कमी होने से कृषि अवसंरचना व्यय व्यर्थ जाने की संभावना है।

(ii) मंद अर्थव्यवस्था → मंदी → कम मांग
→ कार खरीद कम → सड़क पर व्यय का अनुत्पादक सभाव

(iii) सरकारी खर्च अधिक : → रू निर्गमन →
अब यदि आपूर्ति कम होगी तो मुद्रास्फीति का
प्रभाव हो सकता है।

किंतु वसरा दूसरा पक्ष भी है कि-
अवसंरचना विपरीत - आपूर्ति पक्ष बढ़ाता है जैसा
कि 1929 की आर्थिक मंदी के बाद रुज्जुवेल
के न्यू डील कार्यक्रम में देखा गया।

(ii) चीन की उत्पादन क्षमता
में वृद्धि का प्रमुख कारण इसकी प्रभावी
आपूर्ति श्रृंखला अव्यवस्था है।

अतः अवसंरचना विपरीत अव्यवस्था
वृद्धि के साथ-साथ आपूर्ति बढ़ाने में
मद्दगार है वशात -

- (i) व्यय लक्षित है।
- (ii) परिणाम आधारित है।
- (iii) सामाजिक व्ययों : शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल
विकास की हानि पर न है।

14. Innovations emerge not just as an opportunity but also as a pre-condition to assure the sustainability of food production. Analyse the statement in context of the food processing sector in India. (250 words) 15

नवाचार, खाद्य उत्पादन की संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए न केवल एक अवसर के रूप में बल्कि एक पूर्व शर्त के रूप में भी उभरें हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संदर्भ में, इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

समावेशी व संधारणीय उत्पादन तंत्राली से तात्पर्य है कि खाद्य उत्पादन इस प्रकार से करना ताकि वह जलवायु अनुकूल हो व ~~ब~~ दालिया व भविष्य की पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे।

नवाचारों का महत्व : पूर्व शर्त के रूप में]

(i) खाद्य उत्पादन सृजन -

↳ बिना खाद व कीटनाशकों के GM तकनीक का प्रयोग करना।

(ii) भ्रूषमरी को समाप्त करना

↳ फूड कोर्टिकिकेशन

(iii) भोजन की वर्गदारी कम करना

↳ फूलिंग, खाद्य परिवर्तन तंत्राली - पोस्ट पोस्ट लॉस कम करने में।

(iv) प्रसंस्करण में :- उत्पादों को इस प्रकार

परिमित करना जिससे उनके पोषक-तत्वों में सुधार हो (गुण न बदले)

• जेम-धैली निर्माण।

• आयोडीन नमक, Iodon युक्त दूध।

इस प्रकार पूर्वशर्त के रन्य में नवाचारों का संयोग उनके सार से लाभ देता है।

अक्सर के रन्य में नवाचार

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तकनीक सृजन

→ तकनीकी आपूर्ति शृंखला (ब्लॉकचेन संयोग)

→ रीफर व इलिंग वेन।

→ किसान सूचना प्रणाली → सिखा

कूड पार्क जुड़ाव।

(ii) आजीविका सृजन - किसानों की अतिरिक्त

आमदनी का स्रोत :-

(iii) निर्यात संवर्धन :- द्वितीय के प्रतिबंध मानकों

द्वि-नवाचारी परिरक्षण उपाय :-

- नैनो तकनीकी आधारित परिरक्षण - नैनो चाँदी

- पराबैंगनी किरण परिरक्षण।

(iv) सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में

नवाचार → संघारणीय योजना

- जरीबी निवारण
- मुख्यमरी निवारण
- सतत हृषि ।

(v) खाद्य प्रसंस्करण की सरकारी योजना का
उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु तकनीक आधारित

दस्तावेज :-

→ मेगा फूड पार्क (PMKSY)
→ तकनीकी निगारणी ।

इस प्रकार भारतीय नवाचारी संस्कृति
न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उन्नति
हेतु आवश्यक है अपितु संपूर्ण खाद्य
पूणाली की संघारणीयता हेतु उपयुक्त है

15. The factors contributing to unemployment in India are not merely a result of the structural issues related to the Indian economy. Discuss. Also, highlight the measures taken to address the problem of unemployment in recent times. (250 words) 15

भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले कारक केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों का परिणाम नहीं हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, हाल के दिनों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डालिए।

हालिया आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार
भारत की बेरोजगारी दर 4.8% है।

भारत में बेरोजगारी के कारक

(i) संरचनात्मक कारक - तर्क दिया जाता है कि
ये कारक सबसे प्रमुख हैं जैसे -

(क) विकास मॉडल की चुनौतियाँ :- रुधिर से
सेवा की ओर गमन।
— उद्योग में रोजगार का अभाव।

(ख) रुधिर में रोजगार कम नहीं हुए हालाँकि
इसका GDP में योगदान कम नहीं हुआ।

(ग) रोजगार सृजक क्षेत्रों पर कम ध्यान
↳ वस्त्र, लौह आदि।

किंतु केवल ये कारक ही नहीं, अन्य
भी कारक हैं जो जिम्मेदार हैं -

(i) शिक्षा व्यवस्था - तृतीय शिक्षा में 3 नामांकन
केवल 26% हैं।

- (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों का खराब निष्पादन।
- (iii) संस्थानों का पुराना पाठ्यक्रम :: नियोजनीयता का कम प्रतिफल :- भारत कौशल रिपोर्ट -
भारत के केवल 46% स्नातक रोजगार योग्य हैं।
- (iv) विनियामकीय बाधाएँ : EPFO, ESIC नियम।
• कर्मों पर अधिक रोजगार द्वारा = अनुपालन ↑
- (v) अनौपचारिकता व असंगठित रोजगार की समस्या
- (vi) महिला रोजगार दर कम :: PLFS = 23%.

भारत सरकार के उपाय

- ① कानूनी पक्ष - श्रम संहिताओं का निर्माण करना
- MSME की परिभाषा में संशोधन।
- वेतन (न्यूनतम) सुधार।
- ② योजनाएँ
→ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना।
→ कौशल विकास मिशन
- PM कौशल विकास योजना।

• उत्पादन लिंक होल्साहन (PLI) योजना)

- ③ सुधार → शिक्षा नीति 2020
↳ व्यावसायिक शिक्षा +
↳ कौशल विकास योजना 3.0 .
↳ राष्ट्रीय प्रतिष्ठित होल्साहन योजना में
संशोधन का वजलीय प्रावधान ।

④ ई-श्रम पोर्टल व सामाजिक सुरक्षा कोष
↳ औपचारिक रोजगार सुधार व सुरक्षा ।

⑤ महिला रोजगार: श्रम संस्था में समान
जवाबदारी का प्रावधान ।

आगे की रणनीति (i) राष्ट्रीय रोजगार नीति लाना)

(ii) रोजगार गहन क्षेत्र विकास
↳ खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा आदि ।

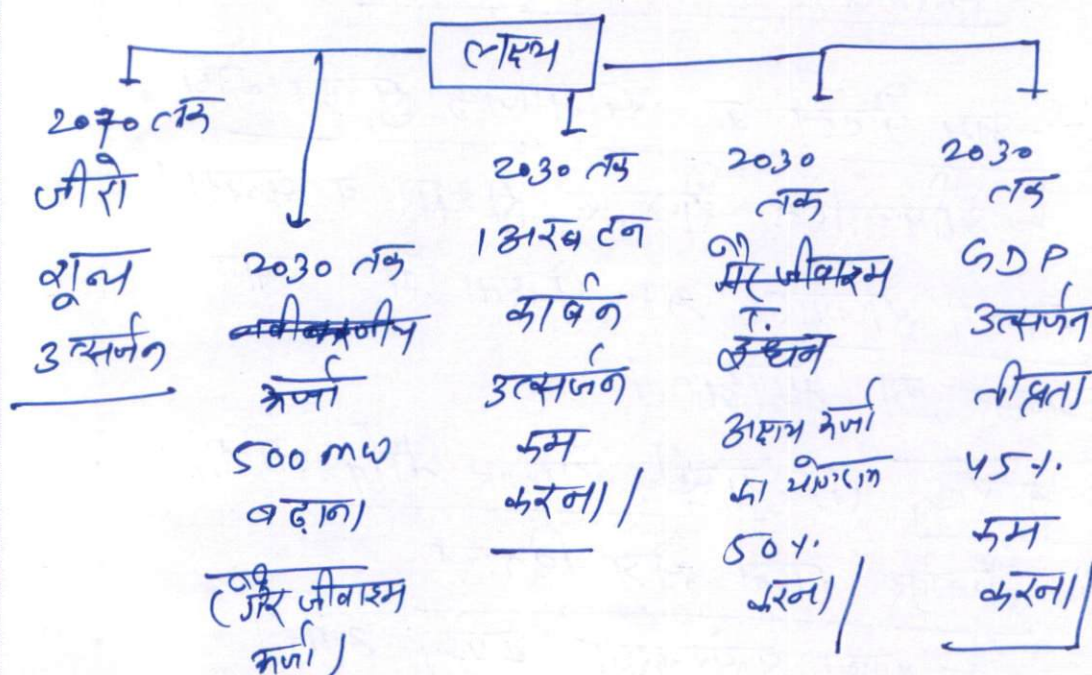
(iii) नई तकनीकी उद्योग 4.0 के अनुरूप
कौशल विकास ।

हर वर्ष उद्योग युवा लैबर कोर्स में
स्मारित होते हैं जहाँ कौशल रोजगार
हेतु उपर्युक्त समाधान आवश्यक हैं

16. Highlighting the major announcements made by India in the recently concluded COP26, examine India's capabilities in achieving net zero emissions by 2070. (250 words) 15

हाल ही में संपन्न COP26 में भारत द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने में भारत की क्षमताओं का परीक्षण कीजिए।

हाल ही में भारत ने COP 26 में भारत ने पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की।



शून्य उत्सर्जन हेतु भारत की समता।

① कार्बन उत्सर्जन में 5M :- CSE की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-16 के मध्य उत्सर्जन क्षमता में 25% 5M की है।

② भारतीय उपाय
• NAPCC

• राष्ट्रीय ग्रीन मोबिलिटी मिशन।

③ उत्सर्जन कम करना

- ↳ उद्योगों (ताप विद्युत संयंत्रों) पर उत्सर्जन मानक लागू करना।
- ↳ CCS व CCUS प्रौद्योगिकी अपनाने पर प्रोत्साहन।

④ नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

- ↳ श. सौर मिशन :- कुल ऊर्जा
- ↳ कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 26-1. है (टाइडो को टाइडर)
- ↳ सौर विनिर्माण में तेजी।
- ↳ राष्ट्रीय आपतरीय ऊर्जा नीति।

④ स्वच्छ ईंधन व परिवहन

- ↳ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति।
- ↳ नीति आयोग का मैथेनॉल इफोनॉमी कार्यक्रम।
- ↳ इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम।

⑤ अवसंरचना व बिल्डिंग

- ↳ ऊर्जा संरक्षण/अवन संहिता
- ↳ ग्रीन हाइव निर्माण।

⑥ दमिती इच्छा :- राष्ट्रीय स्तर पर सतत इच्छिमिरान।

चुनौतियाँ ① वित्त - MoEFCC के अनुसार भारत के पेरिस समझौता लक्ष्य पूरा करने हेतु प्रति वर्ष 11 ट्रिलियन ₹ आवश्यक।

② तकनीक - हाइड्रोजन तकनीक।

↳ CC5 तकनीक।

↳ विकसित देशों की प्रविष्टता नहीं।

③ मौखला संचयनों पर बढ़ती निर्भरता

• 56% कर्जा मौखले से

• Path largest रिजर्व।

④ निजी क्षेत्र सहयोग कमी।

आगे की राह :- अर्थों की पूर्वापेक्षा -

• हरित वित्त तक पहुँच है (Green Bond)

• हरित तकनीक तक पहुँच है।

• ISA व CDRI जैसे संघों का प्रयोग

• Green Ag जैसे परियोजनाओं का सहायी उपयोग।

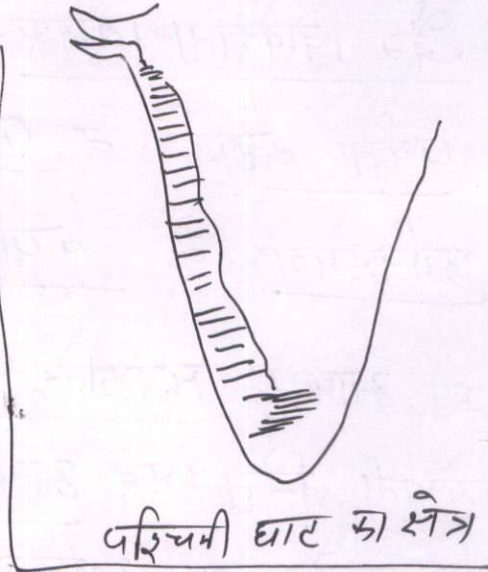
• अन्तर्देशीय सहयोग आवश्यक।

इस प्रकार उपर्युक्त पूर्वापेक्षाओं के साथ सरकार के सभी स्तरों पर सहायी प्रयासों की आवश्यकता है।

17. While geography plays a definite role in the recurring disasters in Western Ghats, it is the human intervention that has exacerbated them. Discuss. Also, suggest measures to protect Western Ghats from these frequent disasters. (250 words) 15

यद्यपि, पश्चिमी घाट में बारंबार आपदाओं के घटित होने के पीछे भौगोलिक स्थिति एक निश्चित भूमिका निभाती है, तथापि मानवीय हस्तक्षेपों ने उन्हें और बढ़ा दिया है। विवेचना कीजिए। साथ ही, बार-बार आने वाली इन आपदाओं से पश्चिमी घाट को बचाने के उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत के पश्चिम तट के
समानान्तर 1600 किमी में
 फैला पश्चिमी घाट पर्यावरण
की दृष्टि से अत्यन्त
महत्वपूर्ण है
• जैव विविधता हॉटस्पॉट



आपदाओं में भौगोलिक स्थिति की भूमिका

- (i) भू-स्वतंत्र क्षेत्र
- (ii) पर्वतीय वर्षा की अधिकता - बाढ़
- (iii) भू-कंप क्षेत्र - (जॉन 5)
- (iv) भू-भ्रंशों की उपस्थिति

मानवीय हस्तक्षेपों का समाव

- (i) तीव्र जनसंख्या वसाव - विश्व के समस्त हॉटस्पॉटों में सर्वाधिक स्थान धारण।

- (ii) अवैध खनन व लकड़ी कटाई।
- (iii) पर्यावरणीय आकलन के बिना
निर्माण कार्य :- हॉटल आदि।
- (iv) जैव विविधता शिकार
- (v) पर्वत कटाई व सड़क निर्माण
- (vi) अतिक्रमण व बसावट क्षेत्र

कोई भी आपदा प्राकृतिक रूप से नुकसान
नहीं पहुँचाती किंतु जब आपदा प्रवण क्षेत्र में
मानवीय हस्तक्षेप व अतिक्रमण होता है तो
यह नुकसान का कारण बनती है।

सुझाव

- ① पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र धींचित
करना :- संवेदी क्षेत्र संरक्षण।
- ② अवैध, खनन, निर्माण पर रोक लगाना।
- ③ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बाद
ही कोई परियोजना शुरू करना।

④ स्थानीय लोग भागीदारी

- ↳ हरि बंध निर्माण।
- ↳ जल संचयन क्षेत्र विकास करना।
- ↳ आपदा संबंधन (बचाव, रिकवरी में भागीदारी)।
- ↳ सभावी हरिक्षण दिया जाय।

⑤ नदियों पर अतिक्रमण रोकना व जल संरक्षण उपाय अपनाना।

⑥ जंगलों की कटाई नियंत्रण

- ↳ उपग्रह निगरानी।
- ↳ वन अधिकारी हरिक्षण।

उपयुक्त उपायों के साथ गाडगिल समिति के सुझावों को लागु करना उचित उपाय है क्योंकि अस्तित्व व विकास में अस्तित्व पहले है और विकास का कार्य सभाक पर्यावरण की शर्त पर नहीं हो सकता।

18. The IPR regime in India is mired by inadequate protection and ineffective implementation. In this context, discuss how the IPR regime can be made more robust and effective. (250 words) 15

भारत में IPR प्रणाली अपर्याप्त संरक्षण और अप्रभावी कार्यान्वयन से ग्रस्त है। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि IPR प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।

हालिया ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में पिछले 5 वर्षों में लगभग 45 अंकों का सुधार हुआ है।

2014 = 80 +
2020 = 48 नीं

IPR प्रणाली : चुनौतियाँ

① अपर्याप्त संरक्षण

- (i) प्रभावी कानूनों का अभाव।
- (ii) IPR जागरूकता का अभाव।
- (iii) IPR परिसीमित स्वतंत्र अधिकारियों की अनुपस्थिति
- (iv) राष्ट्रीय IPR नीति के प्रावधानों में वास्तविकी प्रावधानों का न होना।

(v) कॉपीराइट उल्लंघन

- ↳ फर्जी फिल्म पोस्टरों उल्लंघन।
- ↳ टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर

फिल्में, धारावाहिकों का अंधाधुंध प्रचार।

(vi) पैटेंट अधिनियम

↳ धारा 3(v) के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग
का मुद्दा।

अज्ञाती कार्यान्वयन

↳ जर्मा कंपनियों में ज्ञाती IPR नियमों
में क्रियान्वयन नहीं।

↳ TRIPS + के युग में TRIPS प्रावधानों
का पूर्णतः कार्यान्वयन नहीं।

मजबूत बनाने के उपाय

① विनियमन :- IPR स्वतंत्र हेतु पर्याप्त विनियमन
(संगठन व स्वतंत्र अधिकारियों हेतु) की
व्यवस्था की जाये।

② IPR नीति का अमरशा: क्रियान्वयन करना
↳ वास्तविकी समग्रवर्द्ध लक्ष्य घोषित करना।
↳ ज्ञाती स्वतंत्र तंत्र विनियमित करना।

③ ज्ञाती IPR प्रोफेशनल मनी करना

④ साक्षर विम्वर समता मजबूती :- केरल पुलिस
के साक्षरता प्रोजेक्ट द्वारा कर्ना

फिल्म रैंडर को बकस जाना।

5) द्वीकृत संरचना के साथ सभावी IPR
साधिकरण का निर्माण

↳ अलग-2 विभागों में विखंडित संरचना
↳ समन्वय की कमी।

6) IPR जागरूकता व आवेदन दायित्व प्रक्रिया
का सरलीकरण करना।

भारत को आने वाले विश्व के
IPR नियमों TRIPS + सावधानों के
अनुरण्य खुद की क्षमता को विकसित करना
चाहिये। साथ ही जन विकास, स्वास्थ्य जैसे
अपान मुद्दों पर स्पष्ट सावधान व राय भी
रखनी चाहिये।

19. What are the similarities and differences between the activities of terrorists and organized criminal groups? Also, elaborate upon the fact that their linkages occur in both tactical and strategic ways. (250 words) 15

आतंकवादियों और संगठित अपराधिक समूह की गतिविधियों के बीच समानताएं और असमानताएं क्या हैं? साथ ही, इस तथ्य पर सविस्तार चर्चा कीजिए कि उनके संबंध सामरिक और रणनीतिक दोनों तरीकों से होते हैं।

देश के सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख खतरों के रूप में आतंकवाद व संगठित अपराधों को शामिल किया जाता है।

आतंकवाद	भिन्नता	संगठित अपराध
1. राजनीतिक उद्देश्य		• आर्थिक उद्देश्य
2. सरकारों से संबंध नहीं — विरोधी कार्य		• सरकारों से गठजोड़ की वरीयता।
3. हिंसात्मक कृत्यों की प्राथमिकता।		• सामान्यतः हिंसा नहीं (अपवाद स्थिति में)।
4. मुख्य उद्देश्य सरकारों की अबाधना, हिंसा व भय का सृजन करना।		• मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था गतिविधि से व्यवसाय करना।
5. दखिचारों का प्रयोग।		— आवश्यक नहीं।

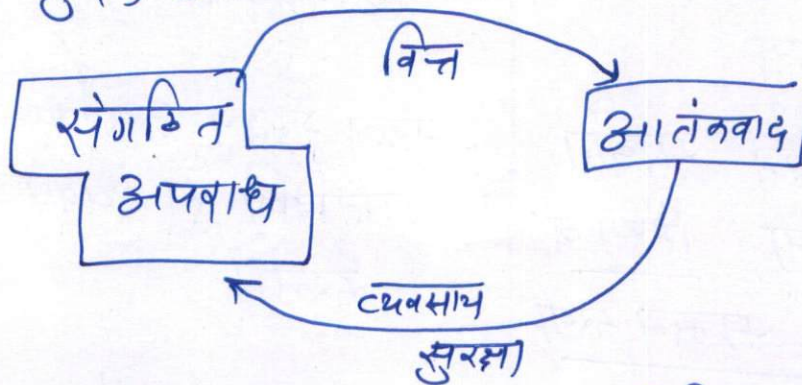
समानता के बिंदु → कई स्तरों पर

- (i) संगठित संरचना का होना।
 (ii) अवैध गति विधियाँ।
 (iii) कमांड के अनेक स्तरों का पाया जाना।
 (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा।
 उदा० आतंकवाद - ISIS, बीकी हरम समूह।
 संगठित अपराध - इंटरवर्ल्ड, मादक द्रव्य संग्रहण।

दोनों के मध्य संबंध

[मुख्यतः तीन स्तर।

- (i) पार्ष्ण्य का स्तर - दोनों का अलग-2
अस्तित्व।
 (ii) पुरक आवश्यकता व समन्वय।



- (iii) एकीकरण का चरण - दोनों सम्मिलित
हो जाते हैं उदा० - दाउद शवाहिम
सी 'डी कंपनी'।

सांख्यिक स्तर पर कारण

- (i) संगठित अपराध को सरकारी ज्यासों से खतरा तो आतंकवाद से सुरक्षा इपाथ।
- (ii) आतंकवाद को सैन्य व वित्त कमी → संगठित अपराध से मदद।

राजनीतिक तरीके

- (i) युंति अवैध गतिविधियाँ हैं
- (ii) परन्तत पूर्ति हेतु लकीकरण
- आर्थिक ↑
 - विचारधारात्मक ↑

उदा० बीपी हरम द्वारा मादक द्रव्य तस्करी

इस प्रकार दौनों का सम्मिलित रूप दोहरी चुनौती पैदा कर इन्हें सद्व्यक्ति शक्तिशाली बनाता है। वैसे लिये सरकारों की कठोर व बहुआयामी राजनीति बनानी चाहिये।

20. There is a view that the 'civil society is emerging as the new frontier of war', in the 4th generation of warfare. Do you agree with this view? Substantiate with logical arguments. (250 words) 15

ऐसा माना जाता है कि नागरिक समाज, युद्ध की चौथी पीढ़ी में एक नए मोर्चे के रूप में उभर रहा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा हाल ही में नागरिक समाज के संदर्भ में लिखी गयी है।
करते हुए इसकी नकारात्मक भूमिका को उजागर किया है।

नागरिक समाज : युद्ध की चौथी पीढ़ी

नागरिक समाज से तात्पर्य है नागरिक समाज से तात्पर्य सामाजिक, धार्मिक संगठनों, स्वयं सेवी समूहों, सक्रियतावादियों आदि विस्तृत समाज समूह से है - (विश्व बैंक)

युद्ध की चौथी पीढ़ी

- (i) अर्थव्यय धन का उपयोग :- युद्ध समय पहले CBI ने आँकड़ों से न्यायालय के समक्ष कहा था कि NCO's में विदेशी फंडिंग आती है जिसका उपयोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जाता है -
- जिससे GDP को 2-3% की हानि होती

द्वै

(ii) सरकार विरोधी आंदोलन-प्लाना

↳ विकास विरोधी आंदोलन - परमाणु
संचयन, बांध निर्माण के मुद्दों पर
उदा० कुडनकुलम परियोजना पर विरोध

(iii) धर्मान्तरण गतिविधियाँ :- अमेरिका के कम्पैशन
इंटरनेशनल को ब्लैक लिस्ट करना।

(iv) सरकार पर अनुचित दबाव :- ग्रीनपीस, जैल
संगठनों पर आरोप।

(v) जवाबदेहिता का अभाव :- केवल 10% NGOs
द्वारा रिटर्न भरा जाना

• राजनीतिकों द्वारा कर्नेट अनिर्वाचित निर्देश
(undetectable typhants की सेवा दी जाना)

किंतु इन सभी अक्षरों कारणों से
कर्नेट चौकी पीढ़ी के युद्ध मार्च के रूप में
नहीं रहा जाना चाहिये क्योंकि -

(i) सरकार के मिथानलापों पर जवाबदेही
निर्माण करते हैं।

- (ii) क्रियान्वयन अंतराल को भरते हैं।
 (iii) जन-जागरूकता सृजन करते हैं।
 (iv) विभिन्न वर्गों की आवाज उठाते हैं।
 (v) राजनीतिक स्वच्छता :- ADR जैसे संघ
का आंदोलन।
 (vi) संश्लिष्टकरण कार्य :- SEWA द्वारा महिला
संश्लिष्टकरण।
 (vii) सरकार सहयोग :- असाक्षि पात्र द्वारा मिड
डे मील क्रियान्वयन।

आगे की राह :- UNFCRA का उचित क्रियान्वयन -

- (i) अथ ARC :- NGO's के सशालन का
विद्वन्धीकरण करना।
 (ii) विज्ज उभार समिति :- पारदर्शिता को बढ़ावा
देना।

उपर्युक्त उपायों व विद्वन्धी सहायता (नकारात्मक)
पर नियंत्रण द्वारा यह सुनिश्चित होगा कि ये
सरकार के सहयोगी हैं, विरोधी नहीं।